शिक्षा के क्षेत्र में लूट और मुनाफ़ाखोरी

शिक्षा के व्यवसायीकरण और इस क्षेत्र में कम पूंजी की लागत पर अकूत मुनाफ़े को देखते हुए विदेशी कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने कैंपस भारत में खोलने का प्रस्ताव रख रहे हैं जिनमें पढ़ने वाले छात्र बिना विदेश गये विदेशी डिग्री धारक बन जायेंगे। अगर ऐसा होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में लूट और मुनाफ़ाखोरी का एक नया आयाम स्थापित होगा।

मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि शिक्षा को धंधा नहीं बनने दिया जायेगा, यानी शिक्षण संस्थानों को मुनाफ़ा कमाने की छूट नहीं दी जायेगी। यह विचार उन्होंने शिक्षा के बदलते स्वरूप पर एक संगोष्ठी के दौरान व्यक्त किया।

सवाल है, ऐसी हवाई घोषणा कर मानव संसाधन विकास मंत्री किसे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? यहां तो आंख के अंधों को भी यह साफ़ दिखाई पड़ रहा है कि शिक्षा का लगभग पूरी तरह व्यवसायीकरण हो चुका है और सरकार की नीतियां इसी व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने वाली हैं। व्यवसायीकरण हो रहा है तो शिक्षा के व्यवसायी इससे भरपूर मुनाफ़ा कमायेंगे कि सदाव्रत बांटेंगे? आज बड़े-बड़े पूंजीपति घराने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षा देने वाले संस्थान धड़ल्ले से खोलते जा रहे हैं। वे करोड़ों-करोड़ रुपये की ज़मीन खरीद कर उस पर आकर्षक शिक्षा की दुकानें खोल रहे हैं और सरकार उन्हें मान्यता दे रही है।

स्थिति तो यह है कि पंच सितारा निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए भारी-भरकम डोनेशन देने को तैयार अभिभावकों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है।

नर्सरी कक्षा में एडमिशन के लिए ऐसी होड़ मचती है कि जैसी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए भी क्या मचती हो। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बिड़ला-अंबानी की रिपोर्ट को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है जिसमें कहा गया है कि शिक्षा को पूरी तरह निजी हाथों में दे दिया जाये और सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं हो कि निजी शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों से कितनी फ़ीस वसूलते हैं। माध्यमिक स्तर की शिक्षा में हालत यह है कि सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन) ऐसे संस्थानों को भी मान्यता दे रही है जिसके पास आधारभूत संरचना का पूरी तरह से अभाव है। ऐसे गली-गली में खुले शिक्षण संस्थानों में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है उसका पता तब चलता है, जब शिक्षकों और शिक्षिकाओं के ज्ञान के स्तर को आंका जाये। ऐसे स्कूलों में किताबें तो बेची ही जाती हैं, हद यह है कि यूनिफ़ॉर्म तक बेचे जाते हैं। अभिभावक बेचारा तो इसी बात से संतुष्ट हो जाता है कि उसका बच्चा पीठ पर भारी-भरकम थैला लादे यूनिफ़ॉर्म पहने स्कूल आता-जाता है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए ट्यूशन पढ़ना अनिवार्य है। अगर कोई बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता है तो कक्षा में दिया काम पूरा नहीं कर पायेगा और परीक्षा में फेल हो जायेगा।

सवाल है, फ़िर कक्षा में उन्हें पढ़ाया क्या जाता है? कक्षा में बच्चों को काम और सिर्फ़ काम दिया जाता है। यह देखने की जरूरत नहीं समझी जाती कि बच्चे ने पाठ को समझा या नहीं। यहां शिक्षकों-शिक्षिकाओं का भारी शोषण होता है। उन्हें तनख़्वाह के रूप में अधिकतम पंद्रह सौ से दो हज़ार रुपये तक दिये जाते हैं। इसी से समझा जा सकता है कि इतनी कम तनख़्वाह में पढ़ाने वाले कैसे शिक्षक मिल सकते हैं। इधर स्कूल को फ़ीस के साथ किताबों, यूनिफॉर्मों की बिक्री और बच्चों को लाने-ले जाने वाहनों से भी मुनाफ़ा होता है। हर साल ये संस्थान फ़ीस में बढ़ोत्तरी भी कर देते हैं।

यह तो हुई शिक्षा के छोटे दुकानों की बात। बड़ी दुकानों का ज़लवा तो कुछ और ही है। इंटरनेशनल कहे जाने वाले इन स्कूलों में कक्षायें तक एयरकंडीशंड होती हैं। साथ ही कुछ कक्षायें सामान्य भी होती हैं। इन कक्षाओं में वे छात्र बैठाये जाते हैं जो एयरकंडीशंड कक्षा में बैठने की अतिरिक्त फ़ीस नहीं देना चाहते। पढ़ाने के अलावा शिक्षा की इन बड़ी दुकानों में घुड़सवारी से लेकर तैराकी तक का प्रशिक्षण दिया जाता है और हर संभव यह कोशिश की जाती है कि उच्चवर्गीय अभिभावकों की जेब जहां तक हो सके, कतर ली जाये।

सवाल है कि शिक्षा को जब व्यवसाय का दर्जा मिल गया हो और इन व्यवसायियों ने स्कूल-कॉलेजों की स्थापना में करोड़ों-करोड़ रुपयों का निवेश किया हो तो वे मुनाफ़ा कमाना क्यों नहीं चाहेंगे? जो भी स्कूल अथवा कॉलेज जितनी अधिक पूंजी का निवेश करेगा, वह उसी अनुपात में मुनाफ़ा भी कमायेगा और सवाल है, क्यों न कमाये?

आज तकनीकी शिक्षा देने वाले उच्च स्तरीय संस्थानों की जो बाढ़ आ गई है, वह क्यों?

इसके पीछे सरकार की शिक्षा नीति ही काम कर रही है। इन महंगे संस्थानों में शिक्षा पाना अब मध्यमवर्गीय विद्यार्थियों के सामर्थ्य से बाहर की बात हो गई है। वैसे पहले भी स्थिति कोई बेहतर नहीं थी। पर अब तो शिक्षा के हर स्तर पर निजी पूंजी को खुल कर खेलने की छूट दे दी गई है। साथ ही पूंजीपतियों की आवश्यकता को देखते हुए सिर्फ़ तकनीकी शिक्षा को ही बढ़ावा दिया जा रहा है और वर्तमान शिक्षा संस्कृति में मूल्यहीनता चरम पर पहुंच गई है। मानविकी विषयों में शिक्षा को हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इतिहास, दर्शन, मानव विज्ञान, भाषा और साहित्य का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी पूंजीपतियों के लिए किसी काम के नहीं हैं। जहां तक तकनीकी शिक्षा का सवाल है, उसमें भी भारत कई विकासशील देशों से पिछड़ा हुआ है। प्रति एक हज़ार की आबादी में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ब्राजील में जहां 26 है, भारत में 3.6 है। चीन जो भारत की आजादी के दो साल बाद आजाद हुआ, वहां उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या भारत की तुलना में ढाई गुना ज़्यादा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट (2002) के अनुसार हमारे देश में विश्वविद्यालय स्तर की 290 संस्थायें, 13,150 कॉलेज, 4.27 लाख शिक्षक और 88 लाख उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र हैं।

इन आंकड़ों को सामने रख कर सरकार अपनी पीठ स्वयं थपथपाती है, पर देश की जनसंख्या को देखते हुए ये आंकड़े दिखाते हैं कि अन्य विकसित अथवा विकासशील देशों की तुलना में हम कहीं बहुत ही पिछड़े हुए हैं। आज के आंकड़े बताते हैं कि देश के 93 प्रतिशत युवा उच्च शिक्षा से वंचित हैं। जहां तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की बात है, वहां का हाल तो बहुत बुरा है। सरकार सर्वशिक्षा अभियान चला रही है जो महज़ काग़ज़ों पर ही चल रहा है और इस नाम पर खर्च किया जाने वाला लगभग पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इसके अलावा सरकार गरीब बच्चों को खिचड़ी खिला कर शिक्षित करने का प्रयास कर रही है जो अत्यंत ही हास्यास्पद है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार मात्र 22 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन कॉलेज तक 2.60 करोड़ बच्चे ही पहुंच पाते हैं। शेष 19 करोड़ बच्चे बीच में ही शिक्षा छोड़ देने पर विवश हो जाते हैं।

सरकार उच्च शिक्षा हो या प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षा, इस पर खर्च बढ़ाने के बजाय और कम ही करती चली जा रही है। उदाहरण के लिए 1980 तक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाता था, पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के आते-आते यह खर्च 0.3 प्रतिशत रह गया।

एक बात और। जितने भी मुनाफ़ाखोर निजी संस्थान इस देश में चल रहे हैं, उनके मालिकों और संरक्षणदाताओं में राजनेताओं की संख्या काफ़ी है। इसके अलावा रह गये फ़र्जी संस्थान जो प्रचार के दम पर अपना धंधा चलाते हैं। ऐसे अनेकों संस्थान हैं जिन्हें तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता नहीं मिली पर वे झूठी बात कह कर कि उन्हें मान्यता प्राप्त है, अपनी दुकान खोल कर बैठ गये और लाखों में फ़ीस लेकर छात्रों का नामांकन भी कर लिया, पर दो-तीन वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी जब उन्हें मान्यता नहीं मिली तो वे अपना ताम-झाम समेट कर भाग खड़े हुए। रह गये विद्यार्थी तो उनका बहुमूल्य समय तो बर्बाद हुआ ही, उनके पैसे भी लुट गये। सरकार ऐसे फ़र्जी संस्थानों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। आज भी दक्षिण भारतीय राज्यों में ऐसे गैर मान्यता प्राप्त संस्थान अपने विज्ञापनों के माध्यम से छात्रों को धोखा देने की पूरी कोशिश करते हैं।

शिक्षा के व्यवसायीकरण और इस क्षेत्र में कम पूंजी की लागत पर अकूत मुनाफ़े को देखते हुए विदेशी कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने कैंपस भारत में खोलने का प्रस्ताव रख रहे हैं जिनमें पढ़ने वाले छात्र बिना विदेश गये विदेशी डिग्री धारक बन जायेंगे। अगर ऐसा होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में लूट और मुनाफ़ाखोरी का एक नया आयाम स्थापित होगा।

– प्रतिनिधि

जनवाद के लिए क्रांतिकारी विरासत से मुखातिब पाक के छात्र

पाकिस्तान की जनता की जनवाद की आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं हुईं। एक के बाद एक कई फौजी तानाशाहों के बूटों तले पाकिस्तानी जनता रौंदी जाती रही। अमेरिकी साम्राज्यवादी हमेशा पाकिस्तान में अपनी टांग फंसाए रहे। फौजी हुक्मरानों का शासन रहा हो या अल्पजीवी लोकतांत्रित सत्ता का। सभी अमेरिका की कठपुतली बने रहे। अमेरिका की मदद से वहां धार्मिक कट्टरपंथ की नई पौध लगातार तैयार की जाती रही। धार्मिक कट्टरपंथ ने पाकिस्तानी समाज में बची खुची आज़ादी अथवा जनवाद को भी चट कर डाला। इस तरह पाकिस्तान की तकदीर लोकप्रिय भाषा में 3ए (आर्मी, अमेरिका व अल्लाह) से तय होती रही।

आज पाकिस्तान में नए सिरे से जनवाद स्थापित होने की बातें की जा रही हैं। अतीत में भी जनता की जनवादी आकांक्षाओं की नाव पर सवार होकर कई सरकारें आईं। लेकिन ये सरकारें अमेरिका के इशारों पर नाचने वाली ही साबित हुईं। वर्तमान में पाकिस्तान में जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की बात की जा रही है वह भी अमेरिका द्वारा नियंत्रित व निर्देशित है। हालांकि यह सरकार जनता की जनवादी आकांक्षाओं को भुनाकर सत्ता में आई लेकिन इसकी अमेरिका परस्ती का आलम यह है कि यह अपनी ही जमीन पर अमेरिकी हमलों का विरोध नहीं कर पाती। देश की संप्रभुता का अमेरिका द्वारा खुला अतिक्रमण चुपचाप बर्दाश्त करती है। यही नहीं अमेरिका के कहने पर अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ती है। दूसरी ओर इस सरकार की रुचि न तो जनवादी संस्थाओं के विकास में है और न ही पाकिस्तान को धार्मिक कट्टरपंथ व सामंती मूल्य मान्यताओं से मुक्त करने में है।

ऐसे में वास्तविक जनवाद के लिए पाकिस्तान की नौजवान पीढ़ी अपने अतीत की क्रांतिकारी विरासत की ओर मुखातिब हो रही है। अपने अतीत के गौरवशाली संघर्षों व उनके नायकों को याद कर उस परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रही है।

पाकिस्तान के कराची शहर में जनवरी माह में भारी संख्या में छात्र नौजवान एक गौरवशाली आंदोलन व उसके नायक को याद करने के लिए जुटे। यह गौरवशाली घटना थी 1953 का जुझारू छात्र आंदोलन और इसके नेता थे डॉ. मुहम्मद सरवर। डॉ. मुहम्मद सरवर का विगत साल निधन हो गया था। डॉ. मुहम्मद सरवर को श्रद्धांजलि देने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता था कि उनकी ऐतिहासिक विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जाए तथा 1953 के जुझारू छात्र आंदोलन की परंपरा को आगे बढ़ाने का विकल्प लिया जाए। कराची में सैंकड़ों की तादाद में छात्र नौजवान तथा 1953 के छात्र आंदोलन में भागीदार रहे लोग दरअसल इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिए हुए थे।

1953 का साल पाकिस्तान के छात्र आंदोलन में एक क्रांतिकारी उभार का वर्ष था। इस्लामी राज्य का जुनून तथा बंटवारे के बाद भड़की नफरत सब खत्म हो चली थी। उसकी जगह छात्रों नौजवानों के भीतर राष्ट्र निर्माण की भावना, एक संपन्न, प्रगतिशील जनवादी राज्य के सपने आकार ले रहे थे। लेकिन सत्तासीन शासक के लिए युवा पीढ़ी के ये सपने निरर्थक थे। युवा पीढ़ी के सपनों-आकांक्षाओं से अलग नए शासक भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। 1953 का छात्र आंदोलन पाकिस्तान के छात्रों नौजवानों की भावनाओं का विस्फोट था।

एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी छात्र आंदोलन की शुरुआत कराची शहर से हुई। कराची के कालेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने, बेहतर शिक्षण सुविधाओं की मांग को लेकर जनवरी माह में एक दिन कराची में छात्रों का एक विशाल प्रदर्शन हुआ। गौरतलब है कि पाकिस्तान के अस्तित्व में आने से पूर्व कराची कॉलेज बम्बई विश्वविद्यालय से संबद्ध था। पाकिस्तान बनने के बाद यह कॉलेज किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं था। बहरहाल छात्रों के इस आंदोलन को सरकार ने बेरहमी से कुचला। तीन छात्र पुलिस की गोली के शिकार हुए। दर्जनों घायल हुए। इस दमन के प्रत्युत्तर में पाकिस्तान के तमाम कॉलेजों व शहरों के छात्र अगले दिन सड़कों पर आ गए। सशस्त्र बलों और छात्रों के बीच पूरे पाकिस्तान भर में झड़पें हुईं। तीन दिन तक लगभग पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू लगा रहा। पूरे माह भर तक आंदोलन उग्र रूप से चलता रहा। इस दौरान बर्बर पुलिस दमन व गोलाबारी में 23 छात्र मारे गए, सैंकड़ों घायल हुए तथा एक हजार के लगभग छात्र जेल में ठूंस दिए गए। छिटपुट रूप में पूरे साल भर छात्रों का यह आंदोलन बर्बर दमन के बावजूद जारी रहा।

इस आंदोलन के दौरान मुहम्मद सरवर एक लोकप्रिय, जुझारू छात्र नेता के बतौर स्थापित हुए। मुहम्मद सरवर 'डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फ्रंट से जुड़े थे। 'डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फ्रंट' एक क्रांतिकारी छात्र संगठन था जो प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी पाकिस्तान को अपना लक्ष्य घोषित करता था। उस दौरान छात्रों में प्रगतिशील, जनवादी व चेतना भरने का काम डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट फ्रंट बखूबी कर रहा था। यह एक छात्र पत्रिका 'स्टूडेंट हेराल्ड' भी प्रकाशित करता था। 'स्टूडेंट हेराल्ड' की लोकप्रियता का आलम यह था कि इस पत्रिका के अंकों के लिए छात्र अग्रिम तौर पर धनराशि दिया करते थे।

छात्रों, नौजवानों के भीतर पैठती और गहराती जनवादी, प्रगतिशील चेतना से पाकिस्तानी शासक वर्ग किस कदर भयाक्रांत था वह 1953 के छात्र आंदोलन के क्रूर दमन में तो दिखाई दिया ही। इसके बाद तमाम जनवादी, प्रगतिशील संगठनों पर प्रतिबंध लगाने, कट्टरपंथी तत्वों को आगे बढ़ाने की नीति में भी यह साफ दिखाई दिया। 'पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी' पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 'डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फ्रंट' पर भी पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े होने का आरोप लगाकर प्रतिबंध लगा दिया गया।

जहां एक ओर प्रगतिशील जनवादी व क्रांतिकारी समूहों पर प्रतिबंध लगाकर पाकिस्तानी शासकों ने उनका दमन किया, वहीं कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों को पर्याप्त संरक्षण व फलने फूलने दिया गया। पाकिस्तान के कॉलेज कैंपस शीघ्र ही पतित पूंजीवादी पार्टियों व धार्मिक कट्टरपंथियों की नर्सरी तैयार करने के अड्डे बन गए। पाकिस्तानी शासकों के दमन के बावजूद जनवाद के पाकिस्तानी छात्र नौजवानों का संघर्ष जारी रहा। जनरल अयूब खां को हटाकर लोकतंत्र कायम करने के संघर्ष में छात्रों की अग्रणी भूमिका रही।

कॉलेज कैंपसों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के छात्र गुटों के बीच हिंसक टकराव का बहाना लेकर जनरल जिया उल हक ने कॉलेज में छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगा दिया। छात्र संघ प्रतिबंधित हो गए। जहां तमाम जनवादी व प्रगतिशील तत्वों को कैंपस से प्रतिबंधित कर दिया गया, वहीं जनरल जिया उल हक ने इस्लामी जमात ए जुलबा जैसे कट्टरपंथी छात्र संगठनों को कैंपसों में अपनी गतिविधि चलाने की पूरी छूट दी गई। गौरतलब है कि इस्लामी जमात ए तुल्बा दरअसल जमात ए इस्लामी पार्टी का ही छात्र संगठन था। इस तरह कॉलेज कैंपसों में इस्लामी कट्टरपंथियों का वर्चस्व कायम किया गया। ये तत्व ही भावी तालिबान का भ्रूण रूप थे।

हाल के वर्षों में पाकिस्तान के छात्रों नौजवानों में एक नई राजनीतिक चेतना दिखाई दी है। यह एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के अस्तित्व को कायम रखने, तानाशाही फौजी हुकूमतों से हमेशा के लिए निजात पाने की भावना इस चेतना के मूल में हैं। साथ ही इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों से आजिज आ चुकी नई पीढ़ी जनवाद व प्रगतिशील की ओर मुड़ना चाहती है। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तीन माह तक चले राष्ट्रव्यापी जनान्दोलन में छात्र अग्रिम मोर्चे पर रहे।

यह छात्रों के संघर्ष व आंदोलन की ही ताकत थी कि नवनिर्वाचित पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री गिलानी ने अपने कार्यकाल के सौ दिन के भीतर कॉलेज कैंपसों में छात्र संघ को मान्यता दिलाने अथवा वैध कराने की घोषणा की।

खैर, उस घोषणा को ड़ेढ साल से ऊपर हो चुका है और गिलानी साहब ने इस मसले पर एक आयोग गठित कर उसकी सिफारिश के हवाले छोड़ दिया है। आयोग में शामिल तथाकथित शिक्षाविद फौजी तानाशाहों के युग के ही हैं। वे बार-बार आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि छात्र संघों को वैध करने पर कॉलेज परिसर में फिर से हिंसक गतिविधियों की बाढ़ आ जाएगी। जनवाद को लेकर कितना संशय पाकिस्तान के अकदमीशियनों के बीच है, यह इससे जाहिर है। लेकिन पाकिस्तान के छात्र नौजवान अपनी क्रांतिकारी विरासत की ओर मुखातिब होकर पुरानी पीढ़ी के अधूरे छूटे कार्यभारों को अपने कंधे पर उठाते के लिए तत्पर दिख रहे हैं। उनकी आंखों में एक जनवादी, प्रगतिशील पाकिस्तान को हासिल करने की ललक स्पष्ट दिखाई देती है।

नगेन्द्र मनराल